मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

आयुष्मान का झुनझुना 3
अमेरिका के हाथों गिरवी 4
बोलिए मोदी जी 5
महिलाओं की जीत 8

वर्ष 31 अंक -38 फ़रीदाबाद 16-22 सितम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

धरती लगी फ़टने तो खैरात लगी बंटने

चुनावी बेला में बिजली के दाम घटे, समय आने पर तेल के दाम भी घटेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज्यों-ज्यों लोकसभा के चुनाव निकट आते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की धड़कने तेज होती जा रही हैं। अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा सरकारों ने बिजली, तेल, कोयला, गैस आदि तमाम चीज़ों पर मनमाने टैक्स लगा कर जनता को खूब लूटा है।

हरियाणा की मनोहर सरकार ने फ़िलहाल बिजली के दामों में कुछ राहत देने की घोषणा की है। नये दाम पहली अक्टूबर से लागू करने की बात कही गयी है फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई आदेश बिजली अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुये हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक दाम घटाने से 31 मार्च 2019 तक की छमाही में हरियाण सरकार को करीब 338 करोड़ का घाटा होगा।

दाम घटाने की घोषणा करते हुये सरकार ने यह नहीं बताया कि घोषित दामों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से और क्या-क्या वसूली की जायेगी। विदित है कि जनता को बेवकुफ़ बनाने के लिये सरकार बिजली की दरें तो वही रखती है लेकिन फ़्यूल सरचार्ज के नाम पर जितना चाहे वसूली करती रहती है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि तालिका में दिखाये गये घोषित दामों के अतिरिक्त कोई और वसूली भी की जायेगी या नहीं

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि जिस बिजली को हरियाणा सरकार सात से नौ रुपये प्रति यूनिट तक बेचती आ रही है उसे सरकारी व गैर सरकारी बिजली बनाने वाली कम्पनियों से औसतन ढाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदती है। इसके अलावा हरियाणा को भाखड़ा से जो बिजली मिलती है वह तो और भी सस्ती है। खरीदी गयी इस बिजली को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सरकारी खर्च करीब 6 रुपये पड़ता बताया जाता है। यानी बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनियां अपना पर्याप्त मुनाफ़ा रखने के बाद भी हरियाणा सरकार को ढाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचती हैं लेकिन भ्रष्टाचार और निकम्मेपन में डूबा सरकार का ये विभाग उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने में इसके उत्पादन से भी अधिक खर्च कर देता है।

बनी बनाई बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर होने वाले इस भारी-भरकम खर्चे के पीछे, विभाग में नीचे से ऊपर तक व्याप्त भ्रष्टाचार व उच्चाधिकारियों का निकम्मापन है। इसके चलते 24 प्रतिशत लाइन लॉस यानी 24 प्रतिशत बिजली गायब हो जाती है। ट्रांसमिशन लाइनों व सब स्टेशनों तथा अन्य उपकरणों के माध्यम से पास होने पर पांच प्रतिशत तक लाइन लॉस होना तो समझ आता है। लेकिन 24 प्रतिशत बिजली का गुम हो जाना लाइन लॉस नहीं हो सकता, यह बिजली की खुली चोरी है। वैसे यह लाइन लॉस किसी जमाने में 40-45 प्रतिशत तक भी होता रहा है। जिसे काबू करके 24 प्रतिशत पर लाया गया है। बिजली के जर्जर उपकरण व लाइने भी काफ़ी हद तक लाइन लॉस का उत्तरदायी हैं। लाइन लॉस के अलावा यहां बड़े घाटे का कारण विभागीय खरीदारी में होने वाले बड़े-बड़े घोटाले भी हैं। जिनका विवरण समय-समय पर 'मज़दूर मोर्चा' में प्रकाशित किया जाता रहा है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के पास बिजली उत्पादन के लिये पर्याप्त थर्मल पावर प्लांट हैं। लेकिन इन प्लांटों में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के चलते यहां बिजली उत्पादन की लागत सात रुपये प्रति यूनिट से भी अधिक आती है। सबसे नवीनतम खेदड़ स्थित पावर प्लांट का तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। इसके निर्माण का ठेका धीरू भाई अम्बानी के निकम्मे छोरे अनिल अम्बानी को दिया गया था। यह छोरा दलाली खाने के अलावा कोई काम नहीं करता, लिहाज़ा इसने इस प्लांट के निर्माण का ठेका चीन की शंघाई इलेक्ट्रीक कम्पनी को दे कर अपना मोटा मुनाफ़ा खरा कर दिया। प्लांट इतना घटिया बना है कि पहले दिन से ही यह कभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल पाया। आज भी इसको चलाने पर कमाई कम और घाटा अधिक होता है।

तेल के दाम भी घटेंगे

भारत सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो आज कह रहे हैं कि तेल के दाम सरकार के हाथ में नही है, मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व तेल के दामों में भारी कटौती करेंगे। विदित है कि पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव के दौरान लगभग डेढ महीने तक तेल के दामों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई लेकिन मतदान पूर्ण होते ही धड़ाधड़ तेल के दाम बढा दिये।

लगता है भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही है कि जनता मूर्ख है, इन्हें पौने पांच साल तक जम कर लूटो और आखरी तीन महीने थोड़ी राहत देने से जनता अपने साथ हो चुकी लूट को भूल जायेगी। अब यह तो चुनाव परिणाम ही बतायेंगे कि जनता मूर्ख है या भाजपा का आकलन मूर्खाना है।

बिजली यूनिट के हिसाब से इस तरह होगा फायदा

खपत	पुरानी दरें (रु.में)	नई दरें	पुराने बिल	नए बिल (अनुमानित)
50 यूनिट	2.70	2.00	135	100
100 यूनिट	3.60	2.50	360	250
150 यूनिट	4.50	2.50	675	375
200 यूनिट	4.69	2.50	938	500
250 यूनिट	4.80	3.05	1200	763
400 यूनिट	5.36	4.27	2145	1708
500 यूनिट	5.55	4.68	2775	2338

जिले में टोटल
5 लाख 8 हजार 349 कंज्यूमर हैं।

डोमेस्टिक कंज्यूमर
4 लाख 20 हजार 987 हैं।

500 यूनिट खपत
वाले 2 लाख 30 हजार कंज्यूमर हैं।

"पिछली सरकार ने उजाड़ा, हमने बसाया"-कृष्णपाल गूजर

नारियल फ़ोड़ने, झूठ बोलने में मोदी-शिष्य का कोई सानी नहीं है

फ़रीदाबाद (म.मो.) रविवार 2 सितम्बर को फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफ़आईए) की 65 वीं आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल गूजर ने कहा कि उनसे पहले की सरकारों ने इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस शहर का पूरे एशिया में पहला स्थान था, आज वह किसी स्थान पर नहीं रहा। गुड़गांव तथा नौयडा जैसे शहर इससे कहीं आगे निकल गये। इसके बावजूद जब (2014) से उनकी मोदी सरकार आई है, शहर का लगातार विकास हो रहा है।

गूजर ने शायद पहली बार सच बोलते हुये कहा है कि इस शहर का एशिया में जो स्थान था वह अब नहीं रहा। लेकिन यह अधूरा सच है। पिछली सरकार का जो समय गूजर जी मान रहे हैं। वह केवल कांग्रेसनीत यूपीए सरकार का है। इससे पूर्व भाजपा नीत एनडीए सरकार के उस समय को नहीं गिनते जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस काल में भी शहर का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गयी थी। इसके अलावा गूजर जी यह भी भूल रहे हैं कि इस शहर को नम्बर एक का दर्जा दिलाने में उनकी भाजपा अथवा जनसंघ का कभी कोई योगदान नहीं रहा। वह सब कांग्रेसी सरकारों का ही किया धरा था।

पुल का निर्माण कार्य 'प्रगति' पर, कभी तो पूरा होगा ही

झूठ बोलने में पारंगत मोदी के पद-चिन्हों पर चलते हुये गूजर महोदय अपने साढे चार साल के शासन में इस शहर को विकसित कर दिये जाने का दावा करते हैं। मंत्री महोदय को समझ लेना चाहिये कि जहां-तहां नारियल फ़ोड़ने व अखबारों में बयान छपवाने से कोई विकास नहीं हुआ करता। जिस मंझावली यमुना पुल से नौयडा और फ़रीदाबाद को जोड़ने का ख्वाब मंत्री जी बीते 4 साल से जनता को दिखा रहे हैं वह अभी ख्वाब ही है। आगामी दो साल तक भी उसके चालू होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। पुल तो जब बनेगा तब बनेगा अभी तो पुल तक पहुंचने के लिये सड़क निर्माण की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। छह लेन के इस पुल तक पहुंचने के लिये फ़िलहाल 5 गांवों के बीच से गुजरती संकरी सड़कें हैं। यदि इन सड़कों को छह लेन का नहीं बनाया गया तो पुल किस काम आयेगा?

बदरपुर बार्डर से लेकर होडल के यूपी बार्डर तक के 73 किलोमीटर राजमार्ग को इतना चौड़ा व सुविधाजक बना दिया गया है कि बिना कहीं जाम के फंसे यात्रा की जा सकती है। गूजर के मुताबिक इस काम पर एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने 160 करोड़ रुपया खर्च किये हैं। यह विशुद्ध झूठ है। करीब 7 वर्ष पूर्व यह काम देश के सबसे बड़े चोर पूंजीपति अनिल अम्बानी की रिलायंस इन्फ्रा कम्पनी को सौंपा गया था। तब से यह चोर इस राज मार्ग पर (आगरा तक) दो जगह टोल नाके लगा कर रोज़ाना करीब एक करोड़ की वसूली कर रहा है। तीसरा टोल नाका बल्लबगढ से निकलते ही गदपुरी पर शुरू होने वाला है। इस मोटी लूट में से कुछ हिस्सा खर्च करके धीरू भाई अम्बानी का यह छोरा इस राजमार्ग पर बीते 7 वर्षों से काम करने के नाम पर खेल-तमाशे कर रहा ह। विदित है कि मौके पर काम करने का ठेका इसने भारत की बड़ी निर्माण कम्पनी लार्सन एंड टुब्रो को दे रखा है। परंतु वह कम्पनी भी तो उतना ही काम करेगी जितना पैसा यह चोर अम्बानी उन्हें देगा और तब ही करेगी जब पैसा आयेगा। पिछले दिनों पैसा नहीं आने के चलते निर्माता कम्पनी श्रमिकों को वेतन नहीं दे पाई तो वे हड़ताल पर चले गये थे।

शेष पेज आठ पर